

अर्थशास्त्र

(समष्टि अर्थशास्त्र)

अध्याय-5: सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था



बजट

यह आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित व्ययों एवं अनुमानित प्राप्तियों का वार्षिक वित्तीय विवरण है।

बजट के मुख्य उद्देश्य

- संसाधनों का पुनः आवंटन
- आय व धन का पुनः वितरण
- आर्थिक स्थिरता
- सार्वजनिक उद्यमों का प्रबन्ध
- आर्थिक विकास
- निर्धनता एवं बेरोजगारी उन्मूलन

बजट के घटक

बजट को दो भागों में बाँटा जाता है :-

1. राजस्व बजट
2. पूंजीगत बजट

राजस्व बजट

राजस्व बजट सरकार की वित्तीय वर्ष में अनुमानित राजस्व प्राप्तियों व राजस्व व्यय का ब्यौरा है।

पूंजीगत बजट

पूंजीगत बजट एक वित्तीय वर्ष में अनुमानित पूंजीगत प्राप्तियों तथा अनुमानित पूंजीगत व्ययों का विवरण है।

बजट प्राप्तियाँ

- इससे तात्पर्य एक वित्तीय वर्ष की अवधि में सरकार की सभी स्रोतों से अनुमानित मौद्रिक प्राप्तियों से है।
- बजट प्राप्तियों को निम्न दो उप – वर्गों में बाँटा जा सकता है :-
 1. राजस्व प्राप्तियाँ
 2. पूँजीगत प्राप्तियाँ।

राजस्व प्राप्तियां

यह वह प्राप्तियां होती है जिनसे सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं होती।

उदाहरण :- (सार्वजनिक क्षेत्र की उद्गमों की आय)

पूँजीगत प्राप्तियां

यह वे प्राप्तियां होती है जिनसे सरकार की देयता उत्पन्न होती है।

उदाहरण :- (सरकार द्वारा ऋणों के माध्यम से कोष प्राप्त करना)

राजस्व प्राप्तियाँ ओर पूँजीगत प्राप्तियां में अंतर

राजस्व प्राप्तियाँ	पूँजीगत प्राप्तियाँ
1. ये सरकार की परिसम्पत्तियों को कम नहीं करती हैं।	1. ये सरकार की परिसम्पत्तियों को कम कर देती है।
2. ये सरकार के दायित्वों में वृद्धि नहीं करती है।	2. ये सरकार के दायित्वों में वृद्धि करती है।
3. ये आवर्ती प्रकृति की होती है।	3. ये आवर्ती प्रकृति की नहीं होती।

प्रत्यक्ष कर

प्रत्यक्ष कर वह कर है जो उसी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जिस पर वह कानूनी रूप में लगाया जाता है। इस कर का भार अन्य व्यक्तियों पर नहीं टाला जा सकता है।

उदाहरण :- आय कर, सम्पत्ति कर।

अप्रत्यक्ष कर

अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो लगाए तो किसी एक व्यक्ति पर। जाते हैं किंतु इनका आंशिक या पूर्ण रूप से भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को करना पड़ता है। इस कर का भार अन्य व्यक्तियों पर टाला जा सकता है।

उदाहरण :- बिक्री कर, मूल्य वृद्धि कर (VAT), GST

बजट व्यय

इससे तात्पर्य एक वित्तीय वर्ष की अवधि में सरकार द्वारा विभिन्न मदों के ऊपर की जाने वाली आनुमानित व्यय से है।

बजट व्यय के प्रकार

बजट व्यय को निम्न दो मुख्य उप वर्गों में बाँटा जाता है,

राजस्व व्यय

पूँजीगत व्यय

राजस्व व्यय

ये सरकार की परिसम्पत्तियों में वृद्धि नहीं करते हैं। ये सरकार के दायित्वों में कोई कमी नहीं करते हैं। जैसे – ब्याज का भुगतान, आर्थिक सहायता, कानून व्यवस्था बनाये रखने पर व्यय आदि। ये आवर्ती प्रकृति के होते हैं।

पूँजीगत व्यय

ये सरकार की परिसम्पत्तियों में वृद्धि करते हैं। सरकार के दायित्वों में कमी करते हैं। जैसे विद्यालय भवनों का निर्माण, पुराने ऋण का भुगतान, वित्तीय परिसम्पत्तियों का क्रय इत्यादि। ये आवर्ती प्रकृति के नहीं होते।

राजस्व घाटा

जब सरकार के कुल राजस्व व्यय उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो।

राजस्व घाटे के प्रभाव

- यह सरकार की भावी देनदारियों में वृद्धि करता है।
- यह सरकार के अनावश्यक व्ययों की जानकारी देता है।
- यह ऋणों के बोझ को बढ़ाता है।

राजकोषीय घाटा

कुल व्यय की उधार रहित कुल प्राप्तियों पर अधिकता।

राजकोषीय घाटा = कुल व्यय – उधार के बिना कुल बजट प्राप्तियाँ

राजकोषीय घाटे के प्रभाव

- यह मुद्रा स्फीति को बढ़ाता है।
- देश ऋण – जाल में फँस जाता है।
- यह देश के भावी विकास तथा प्रगति को कम करता है।

प्राथमिक घाटा

राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटाने से प्राथमिक घाटे का पता चलता है।

प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा – ब्याज अदायगियाँ

प्राथमिक घाटे के प्रभाव

- इससे पता चलता है कि भूतपूर्व नीतियों का भावी पीढ़ी पर क्या भार पड़ेगा।
- शून्य या प्राथमिक घाटे से अभिप्राय है कि सरकार पुराने ऋणों का ब्याज चुकाने के लिए उधार लेने को मजबूर है।
- यह ब्याज अदायगियों रहित राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार की उधार जरूरतों को दर्शाता है।

विनिवेश

सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री विनिवेश है।



Fukey Education

NCERT SOLUTIONS

प्रश्न (पृष्ठ संख्या 89)

प्रश्न 1 सार्वजनिक वस्तु सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए। क्यों? व्याख्या कीजिए।

उत्तर- सार्वजनिक वस्तुएँ ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है जिनकी कीमत का निर्धारण बाजार कीमत तंत्र द्वारा नहीं हो सकता। इनकी संतुलन कीमत व संतुलन मात्रा वैयक्तिक उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच संव्यवहार से नहीं हो सकती। उदाहरण-राष्ट्रीय प्रतिरक्षा, सड़क, लोक प्रशासन आदि। सार्वजनिक वस्तुएँ सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि-

1. सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ किसी उपभोक्ता विशेष तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि इसका लाभ सबको मिलता है। उदाहरण के लिए सार्वजनिक उद्यान अथवा वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय किये जाते हैं तो इसका लाभ सभी को मिलता है, भले ही वे इसका भुगतान करें या न करें। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक वस्तुओं पर शुल्क लगाना कठिन या कहेँ असंभव होता है, इसे 'मुफ्तखोरी की समस्या' कहा जाता है। इससे ये वस्तुएँ अर्बज्य हो जाती हैं अर्थात् भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ता को इसके उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता।
2. ये वस्तुएँ "प्रतिस्पर्धी" नहीं होती, क्योंकि एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के उपभोग को कम किये बिना इनका भरपूर प्रयोग कर सकता है।

प्रश्न 2 राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय में भेद कीजिए।

उत्तर-

	आधार	राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय
1.	अर्थ	राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किये जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है, जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण	पूँजीगत व्यय से सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किये जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है, जिसके फलस्वरूप या तो सरकार की

	होता है और न ही देनदारियों में कमी आती है।	परिसंपत्तियों का निर्माण होता है या देनदारियों में कमी आती है।
2. आवृत्ति	ये भुगतान बार-बार करने वाले प्रकृति के होते हैं।	ये भुगतान एक बार करने वाले प्रकृति के होते हैं।
3. उदाहरण	सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, आर्थिक सहायता, सामाजिक और आर्थिक सहायता पर किये जाने वाले व्यय, सरकारी ऋणों पर ब्याज, अदायगियाँ।	सरकार द्वारा भूमि की खरीद, इमारतों, सड़कों, रेल, मेट्रो ट्रेन, पुल का निर्माण, विदेशी सरकार को दिए गए ऋण, ऋणों का भुगतान, सार्वजनिक उद्यम शुरू करना आदि।

प्रश्न 3 राजकोषीय घाटे से सरकार को ऋण ग्रहण की आवश्यकता होती है। समझाइए।

उत्तर- यह कहना बिल्कुल उचित है कि राजकोषीय घाटे से सरकार को ऋण की आवश्यकता होती है। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है।

सकल राजकोषीय घाटा = कुल व्यय - (राजस्व प्राप्तियाँ + गैर - ऋण से सृजित पूँजीगत प्राप्तियाँ)

हम जानते हैं दोहरे लेखांकन प्रणाली के अनुसार सरकार का कुल व्यय और कुल प्राप्तियाँ बराबर होनी ही चाहिए, क्योंकि सरकार ने जो व्यय किया है उसका भुगतान तो इसे करना ही होगा चाहे वह ऋण लेकर करे चाहे नये नोट छापकर जिसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहा जाता है। अतः राजकोषीय घाटा सरकार की कुल ऋण ग्रहण की आवश्यकता के बराबर होता है।

राजकोषीय घाटा = ऋण से सृजित पूँजीगत प्राप्तियाँ

प्रश्न 4 राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में संबंध समझाइए।

उत्तर- जब राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो इसे राजस्व घाटा कहा जाता है। सूत्र के रूप में,

राजस्व घाटा = राजस्व व्यय - राजस्व प्राप्तियाँ

दूसरी ओर बजट के अंतर्गत जब कुल व्यय कुल प्राप्तियों से अधिक होता है तो इस अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है।

$$\begin{aligned}
 \text{राजकोषीय घाटा} &= \text{कुल व्यय} - (\text{राजस्व प्राप्तियाँ} + \text{गैर - ऋण से सृजित पूँजीगत प्राप्तियाँ}) \\
 &= (\text{राजस्व व्यय} + \text{पूँजीगत व्यय}) - (\text{राजस्व प्राप्तियाँ} + \text{गैर - ऋण से सृजित पूँजीगत प्राप्तियाँ}) \\
 &= (\text{राजस्व व्यय} - \text{राजस्व प्राप्तियाँ}) + (\text{पूँजीगत व्यय} - \text{गैर ऋण से सृजित पूँजीगत प्राप्तियाँ}) \\
 &= \text{राजस्व घाटा} + (\text{पूँजीगत व्यय} - \text{गैर ऋण से सृजित पूँजीगत प्राप्तियाँ})
 \end{aligned}$$

प्रश्न 5

- a) मान लीजिए एक विशेष अर्थव्यवस्था में निवेश 200 के बराबर है। सरकार के क्रय की मात्रा 150 है, निवल कर (अर्थात् इकमुश्त कर से अंतरण को घटाने पर) 100 है और उपभोग $C = 100 + 0.75y$ दिया हुआ है तो संतुलन आय स्तर क्या है?

उत्तर-

$$AD = AS, AD = C + I + G$$

$$AS = y$$

$$\therefore y = 100 + 0.75(y - 100) + 200 + 150$$

$$\therefore y = 100 + 0.75y - 75 + 350$$

$$y - 0.75y = 375, 0.25y = 375$$

$$y = \frac{375}{0.25}, y = \frac{37500}{25}$$

$$y = ₹ 1500 \text{ करोड़}$$

- b) मान लीजिए एक विशेष अर्थव्यवस्था में निवेश 200 के बराबर है। सरकार के क्रय की मात्रा 150 है, निवल कर (अर्थात् इकमुश्त कर से अंतरण को घटाने पर) 100 है और उपभोग $C = 100 + 0.75y$ दिया हुआ है तो सरकारी व्यय गुणांक और कर गुणक के मानों की गणना करें।

उत्तर-

$$\bullet \text{ सरकारी व्यय गुणांक} = \frac{1}{1-b} = \frac{1}{1-0.75} = \frac{1}{0.25} = \frac{100}{25} = 4$$

$$\bullet \text{ कर गुणांक} = \frac{-b}{1-b} = \frac{-0.75}{1-0.75} = \frac{-0.75}{0.25} = -3$$

c) मान लीजिए एक विशेष अर्थव्यवस्था में निवेश 200 के बराबर है। सरकार के क्रय की मात्रा 150 है, निवल कर (अर्थात् इकमुश्त कर से अंतरण को घटाने पर) 100 है, और उपभोग $C = 100 + 0.75y$ दिया हुआ है तो यदि सरकार के व्यय में 200 की बढ़ोतरी होती है, तो संतुलन आय में क्या परिवर्तन होगा?

उत्तर-

$$\text{सरकारी व्यय गुणक} = \frac{\Delta y}{\Delta G} = \frac{1}{1-b}$$

जहाँ, Δy = आय में परिवर्तन

ΔG = सरकारी व्यय में परिवर्तन

$$\text{अतः } \frac{\Delta y}{200} = \frac{1}{1-0.75}$$

$$\Delta y = \frac{200}{0.25}$$

$$\Delta y = \frac{20000}{25} = 800$$

$$\Delta y = ₹ 800 \text{ करोड़}$$

प्रश्न 6 एक ऐसी अर्थव्यवस्था पर विचार कीजिए, जिसमें निम्नलिखित फलन हैं-

$$\alpha) C = 20 + 0.80y, I = 30, G = 50, TR = 100$$

आय का संतुलन स्तर और मॉडल में स्वायत्त व्यय ज्ञात कीजिए।

उत्तर- आय का संतुलन स्तर वहाँ होगा जहाँ,

$$AS = AD, y = C + I + G$$

$$y = 20 + 0.80y + 30 + 50$$

$$y - 0.8y = 100, 0.2y = 100$$

$$y = \frac{100}{0.2}, y = \frac{1000}{2}$$

$$y = ₹ 500 \text{ करोड़}$$

$$\text{स्वायत्त व्यय गुणक} = \frac{1}{1-b}$$

$$\text{जहाँ, } b = MPC$$

$$= \frac{1}{1-0.8} = \frac{1}{0.2} = \frac{10}{2} = 5$$

$$b) C = 20 + 0.80y, I = 30, G = 50, TR = 100$$

यदि सरकार के व्यय में 30 की वृद्धि होती है तो संतुलन आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर- स्वायत्त व्यय में वृद्धि = 30 करोड़

$$\text{स्वायत्त व्यय गुणक} = 5 \text{ अतः } \frac{\Delta y}{\Delta G} = 5$$

$$\Delta y = 150 \text{ करोड़}$$

$$\text{अथवा } y = 20 + 0.80y + 60 + 50$$

$$y - 0.8y = 130, 0.2y = 130$$

$$y = \frac{130}{0.2}, y = \frac{1300}{2}$$

$$y = ₹ 650 \text{ करोड़}$$

c) एक ऐसी अर्थव्यवस्था पर विचार कीजिए, जिसमें निम्नलिखित फलन हैं-

$$C = 20 + 0.80y, I = 30, G = 50, TR = 100$$

यदि एकमुश्त कर 30 जोड़ दिया जाए, जिससे सरकार के क्रय में बढ़ोत्तरी का भुगतान किया जा सके, तो संतुलन आय में किस प्रकार का परिवर्तन होगा?

उत्तर- यदि एकमुश्त कर 30 जोड़ दिया जाए तो,

$$AD = 20 + 0.8(y - 30) + 30 + 50$$

$$AD = 20 + 0.8y - 24 + 30 + 50$$

$$AD = 76 + 0.8y$$

$$\therefore \text{आय संतुलन } y = AD, y - 0.8y = 76, 0.2y = 76$$

$$y = 76 + 0.8y, y = \frac{76}{0.2} = \frac{760}{2} = ₹ 380$$

$$y = \frac{76}{0.2} = \frac{760}{2} = ₹ 380 \text{ करोड़}$$

प्रश्न 7 10% की वृद्धि और एकमुश्त करों में 10% की वृद्धि का निर्गत पर पड़ने वाले प्रभाव की गणना करें। दोनों प्रभावों की तुलना करें।

उत्तर- यदि अंतरण में 10% की वृद्धि हो तो नया।

$$AD = 20 + 0.8(y + 10) + 30 + 50$$

$$\text{संतुलन आय } y = AD$$

$$y = 20 + 0.8y + 8 + 30 + 50$$

$$y - 0.8y = 108, 0.2y = 108$$

$$y = \frac{108}{0.2} = \frac{1080}{2} = ₹ 540 \text{ करोड़}$$

यदि करों में 10% की वृद्धि हो तो नया,

$$AD = 20 + 0.8(y - 10) + 30 + 50$$

$$AD = 20 + 0.8y - 8 + 30 + 50$$

$$AD = 92 + 0.8y$$

$$\text{संतुलन आय } y = AD, y = 92 + 0.8y$$

$$y - 0.8y = 92, 0.2y = 92$$

$$y = \frac{92}{0.2} = \frac{920}{2} = ₹ 460 \text{ करोड़}$$

अतः अंतरण में वृद्धि आय के संतुलन स्तर को बढ़ा देती है जबकि एकमुश्त कर में वृद्धि आय के संतुलन स्तर को कम कर देती है।

प्रश्न 8 हम मान लेते हैं कि $C = 70 + 0.70y_D$, $I = 90$, $G = 100$, $T = 0.10y$ संतुलन आय ज्ञात करो।

उत्तर- a) आय संतुलन वहाँ होगा जहाँ,

$$AS = AD$$

$$y = C + IG$$

$$y = 70 + 0.70(y - 0.10y) + 90 + 100$$

$$y = 70 + 0.7(0.9y) + 90 + 100$$

$$y = 260 + 0.60y, y - 0.60y = 260$$

$$0.37y = 260, y = \frac{260}{0.37}$$

$$y = \frac{26000}{37}, y = 702.702 \text{ करोड़}$$

b) हम मान लेते हैं कि $C = 70 + 0.70y_D$, $I = 90$, $G = 100$, $T = 0.10y$ संतुलन आय पर कर राजस्व क्या है? क्या सरकार का बजट संतुलित बजट है?

उत्तर- संतुलन आय पर कर राजस्व $= 0.19y = 0.10 (702.702)$ नहीं यह संतुलित बजट नहीं है, क्योंकि $G > T$ यह घाटे का बजट है और सरकारी बजट घाटा $(100 - 70.27) = 29.73$ करोड़ के बराबर है।

प्रश्न 9 मान लीजिए कि सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति 0.75 है और अनुपातिक आय कर 20% है। संतुलन आय में निम्नलिखित 4 परिवर्तनों को ज्ञात करो।

1. सरकार के क्रय में 20% की वृद्धि।
2. अंतरण में 20% की कमी।

उत्तर-

1.

$$\text{सरकारी व्यय गुणक} = \frac{1}{1-b} = \frac{1}{1-0.75} = \frac{1}{0.25} = \frac{100}{25} = 4$$

सरकारी व्यय में वृद्धि = 20%

संतुलन आय में वृद्धि = ?

$$\text{सरकारी व्यय गुणक} = \frac{\Delta y}{\Delta G}, y = \frac{\Delta y}{20}$$

$$\Delta y = 80\%$$

2.

$$\text{अंतरण गुणक} = \frac{b}{1-b} = \frac{0.75}{1-0.75}$$

$$= \frac{0.75}{0.25} = 3$$

$$\text{अंतरण गुणक} = \frac{\Delta y}{\Delta TR}$$

$$\frac{\Delta y}{-20} = 3, \Delta y = -60\%$$

अतः आय संतुलन में 60% की कमी होगी।

अतः संतुलन आय में 80% वृद्धि होगी।

प्रश्न 10 निरपेक्ष मूल्य में कर गुणक सरकारी व्यय गुणक से छोटा क्यों होता है? व्याख्या कीजिए।

उत्तर-

$$\text{कर गुणक} = \frac{-b}{1-b}$$

$$\text{जबकि सरकारी क्रय गुणक} = \frac{1}{1-b}$$

b सदैव एक से कम होता है (व्यावहारिक रूप में)

$$\frac{-b}{1-b} > \frac{1}{1-b}$$

प्रश्न 11 सरकारी घाटे और सरकारी ऋण ग्रहण में क्या संबंध है? व्याख्या कीजिए।

उत्तर- सरकारी घाटा एक वर्ष में व्यय के लिए सरकार द्वारा लिए गए आवश्यक ऋणों की मात्रा को उजागर करती है। सरकार द्वारा अधिक ऋण लेने का अर्थ है भावी पीढ़ी के उपकरण और ब्याज का पुनर्भुगतान करने का भार अधिक होता है। वर्ष प्रति वर्ष जब ये ऋण भार अधिक होते जाते हैं तो भावी पीढ़ियों के लिए उपलब्ध साधन कम होते जाते हैं। यह निश्चित रूप से वृद्धि की प्रक्रिया में एक प्रतिबंधक के रूप में काम करेगी। विशेषतः जब सरकार गैर-उत्पादकीय उद्देश्य के लिए ऋण लेती है।

प्रश्न 12 क्या सार्वजनिक ऋण बोझ बनता है? व्याख्या कीजिए।

उत्तर- हाँ सार्वजनिक ऋण एक बोझ बनता है। आवर्ती उधार भावी पीढ़ी के लिए राष्ट्रीय ऋणों को संचित करता है। भावी पीढ़ी को विरासत में एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था मिलती है, जिसमें राष्ट्रीय सकल उत्पाद की वृद्धि निरंतर कम रहती है। इसके फलस्वरूप सकल राष्ट्रीय उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा ऋणों के पुनर्भुगतान या ब्याज भुगतान के लिए खपत होती है और घरेलू निवेश निचले स्तर पर बनी रहती है। जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा राजकोषीय घाटा होने पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जहाँ एक दुश्चक्र जन्म लेता है, उच्च राजकोषीय घाटे के कारण सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर कम होती है और निम्न सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि के कारण राजकोषीय घाटा उच्च होता है। अतः प्राप्तिyaँ संकुचित होती हैं जबकि व्यय में विस्तार होता है। इससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है। राजकोषीय घाटा बढ़ने से सरकारी व्यय का बड़ा हिस्सा कल्याण संबंधी व्ययों पर खर्च किया जाता है।

प्रश्न 13 क्या राजकोषीय घाटा आवश्यक रूप से स्फीतिकारी होता है?

उत्तर- यह हमेशा स्फीतिकारी हो यह आवश्यक नहीं। यदि राजकोषीय घाटे का प्रयोग उत्पादक क्रियाओं के लिए किया गया हो, जिससे अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति में वृद्धि हो तो संभव है कि राजकोषीय घाटा स्फीतिकारी सिद्ध न हो, परंतु वास्तव में सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधार का एक महत्वपूर्ण संघटक भारतीय रिजर्व बैंक है। इसके कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होती है। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के कारण प्रायः कीमत स्तर में वृद्धि होती है। कीमत स्तर में साधारण वृद्धि उच्च लाभों के द्वारा अधिक निवेश को प्रेरित कर सकती है। परन्तु जब कीमत वृद्धि का स्तर भयाप्रद सीमाओं तक बढ़ जाता है, तो इसके कारण-

- आगतों को लागतों में वृद्धि।
- मुद्रा की गिरती क्रय क्षमता के कारण समग्र माँग में कमी होती है। आगतों की लागतों में वृद्धि तथा समग्र माँग में कमी एक साथ मिलकर निवेश में कमी करते हैं, जिसके कारण सकल घरेलू उत्पाद में कमी होती है।

अंततः अर्थव्यवस्था में AD कम होने से अपस्फीति भी हो सकती है और आर्थिक मंदी भी जन्म ले सकती है।

प्रश्न 14 घाटे में कटौती के विषय में विमर्श कीजिए।

उत्तर- घाटे में कटौती के लिए दो विधियाँ अपनाई जा सकती हैं-

- **करों में वृद्धि**- भारत में सरकार कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष करों पर ज्यादा भरोसा करती है। इसका कारण यह है कि अप्रत्यक्ष कर अपनी प्रकृति में प्रतिगामी होता है। इसका प्रभाव सभी आय समूह के लोगों पर समान रूप से पड़ती है।
- **व्यय में कमी**- सरकार ने घाटे में कटौती के लिए सरकारी व्यय को कम करने के लिए कटौती पर बल दिया है। सरकार के कार्यकलापों को सुनियोजित कार्यक्रमों और सुशासनों के माध्यम से संचालित करने से ही सरकारी व्यय में कटौती की जा सकती है। परंतु कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्धनता, निवारण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार के कार्यक्रमों को रोकने से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः पूर्व निर्धारित स्तरों पर व्यय में वृद्धि नहीं

करने के लिए सरकार स्वयं पर प्रतिबंधों का आरोपण करती है। इसके अतिरिक्त सरकार व्यय में कमी करने के लिए जिन क्षेत्रों में कार्यरत है स्वयं को उनमें से कुछ क्षेत्रों से निकाल लेती है। इस प्रकार सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री के द्वारा भी प्राप्तियों में बढ़ोत्तरी करने का एक प्रयास किया जाता है।

प्रश्न 15 वस्तु एवं सेवाकर (GST) से आप क्या समझते हैं? पुरानी कर व्यवस्था के मुकाबले GST व्यवस्था कितनी श्रेष्ठ है? इसकी श्रेणियों की व्याख्या कीजिये।

उत्तर- वस्तु एवं सेवाकर (GST)

सरल शब्दों में, " माल एवं सेवाकर एक ऐसी प्रणाली है, जिसके अनुसार माल या सेवा की पूर्ति की प्रक्रिया में प्रत्येक बिन्दु पर की गई वृद्धि पर ही कर लगाया जाता है। यह मूल्यवर्द्धन पूर्तिकर्ता द्वारा किया जाता है। जीएसटी में माल के विक्रेता और सेवा के प्रदायक दोनों की पूर्तिकर्ता की संज्ञा दी गई है।

भारत सरकार की वस्तु एवं सेवा कर (GST) एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। जिस तरह भारत में दो स्तर की सरकार चलती हैं एक केंद्र स्तर की सरकार तथा दूसरी राज्य स्तर की सरकार, उसी तरह वस्तु एवं सेवा कर (GST) को भी दोनों स्तर पर लागू किया गया है एक केंद्र स्तर पर तथा दूसरा राज्य स्तर पर। भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) को चार भागों में विभाजित किया गया है :-

- IGST – एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर
- CGST – केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर
- SGST – राज्य वस्तु एवं सेवा कर
- UGST – केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर